भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अंतारांकित प्रश्न सं. 2385

जिसका उत्तर 13.03.2025 को दिया जाना है

भारतमाला परियोजना का कार्यान्वयन

2385. श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत अब तक स्वीकृत और पूर्ण की गई परियोजनाओं की संख्या कितनी है तथा इस परियोजना के कार्यान्वयन से सबसे अधिक लाभ पाने वाले राज्य कौन-कौन से हैं;

(ख) इस परियोजना से देश में माल ढुलाई में किस प्रकार वृद्धि होने तथा लॉजिस्टिक्स लागत में किस प्रकार कमी आने की आशा है;

(ग) कुशल माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए इसके अंतर्गत कौन-कौन से विशिष्ट गलियारे विकसित किए गए हैं;

(घ) इन परियोजनाओं का भारत के समग्र लॉजिस्टिक्स अवसंरचना में सुधार पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए इसके अंतर्गत क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) उक्त परियोजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों पर दुर्घटनाओं में कितनी कमी आई है तथा इसके अंतर्गत कितनी ग्रामीण सड़कों का निर्माण और उन्नयन किया गया है;

(छ) राजमार्ग निर्माण में स्मार्ट प्रौद्योगिकियों को शामिल करने के लिए इसके अंतर्गत क्या पहल की गई है; और

(ज) इसके अंतर्गत दूरदराज तथा जनजातीय क्षेत्रों में सड़क संपर्क में सुधार लाने के उद्देश्य से कितनी परियोजनाएं हैं तथा यह ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में किस प्रकार योगदान दे रही हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार द्वारा 2017 में देश भर में 34,800 किलोमीटर की लंबाई को कवर करने वाली भारतमाला परियोजना को अनुमोदित किया गया था। दिनांक 28.02.2025 तक कुल 26,425 किलोमीटर लंबाई वाली परियोजनाएं सौंपी जा चुकी हैं और इनमें से 19,826 किलोमीटर का निर्माण पहले ही हो चुका है। राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख), (घ), (च) और (ज) भारतमाला परियोजना का उद्देश्य देश में लॉजिस्टिक दक्षता और कनेक्टिविटी में सुधार लाना है, जिसमें जनजातीय, आकांक्षी और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों तक कनेक्टिविटी बढ़ाना तथा इन राजमार्गों पर दुर्घटनाओं में कमी लाना और सुरक्षित परिवहन नेटवर्क सुनिश्चित करना शामिल है। हाई-स्पीड कॉरिडोर के विकास से प्रमुख आर्थिक केंद्रों के बीच की यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। इन कॉरिडोर के माध्यम से विभिन्न औद्योगिक केंद्रों, एनएमपी नोड्स, एमएमएलपी, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के लिए हाई-स्पीड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी।

(ग) फरवरी, 2025 तक, 6,669 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का कार्य सौंपा जा चुका है, जिसमें से 4,610 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है।

(ड.) जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का संबंध है, तो इनके कार्य मानकों, दिशानिर्देशों, मैनुअल, भारतीय सड़क कांग्रेस की अभ्यास संहिता के साथ ही सड़क और पुल कार्यों के विनिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं। डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव के चरणों के दौरान आवश्यक सड़क सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। इसके अलावा, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनएच परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, उद्घाटन पूर्व चरण के साथ ही मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी एनएच के नियमित सुरक्षा ऑडिट के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(छ) राजमार्ग निर्माण में कई स्मार्ट तकनीकों जैसे स्वचालित और कुशल मशीन-सहायता प्राप्त निर्माण (एआई-एमसी), एलआईडीएआर और ड्रोन आधारित एनालिटिक्स आदि को अपनाया जा रहा है।

अनुबंध

"भारतमाला परियोजना का कार्यान्वयन" के संबंध में श्री भास्कर मुरलीधर भगरे द्वारा पूछे गए दिनांक 13.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2385 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

भारतमाला परियोजना चरण-I के अंतर्गत सौंपी गई और निर्मित लंबाई का राज्य-वार विवरण		
राज्य	**सौंपी गई परियोजनाओं की लंबाई (किमी)**	**निर्मित लंबाई (किमी)**
आंध्र प्रदेश	1,936	1,070
असम	431	381
बिहार	1,159	672
छत्तीसगढ	471	291
दिल्ली	203	183
गोवा	26	26
गुजरात	1,194	977
हरियाणा	1,058	940
हिमाचल प्रदेश	167	115
जम्मू और कश्मीर	251	131
झारखंड	801	481
कर्नाटक	1,603	1,109
केरल	708	443
मध्य प्रदेश	2,017	1,586
महाराष्ट्र	2,174	1,878
मणिपुर	635	417
मेघालय	170	112
मिजोरम	593	461
नागालैंड	208	157
ओडिशा	967	909
पंजाब	1,553	692
राजस्थान	2,360	2,251
तमिलनाडु	1,476	1,230
तेलंगाना	1,026	793
त्रिपुरा	94	68
उत्तर प्रदेश	2,496	1,964
उत्तराखंड	264	163
पश्चिम बंगाल	385	324
कुल	**26,425**	**19,826**

*****